भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4118

दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

विश्लेषणात्मक संकेतक और सामाजिक-आर्थिक मानदंड

4118. श्री आदित्य यादव:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अत्यधिक औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों और पिछड़े राज्यों के बीच बढ़ती क्षेत्रीय आर्थिक और प्रति-व्यक्ति आय की असमानताओं को मापने, उनकी निगरानी करने तथा उन्हें दूर करने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित किए गए विशिष्ट विश्लेषणात्मक संकेतकों (एनालिटिकल इंडिकेटर्स) और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों (सोशियो-इकोनॉमिक मैट्रिक्स) का ब्यौरा क्या है;

(ख) अत्यधिक कर्ज में डूबे या कम संसाधनों वाले राज्यों द्वारा सामना किए जा रहे राजकोषीय असंतुलन (फिस्कल इमबैलेंस) को ठीक करने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रदान की गई योजना सहायता (प्लानिंग असिस्टेंस) या नीतिगत सिफारिशों की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या नीति आयोग के सहकारी संघवाद सूचकांक (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिकेटर्स) जैसे कि 'राज्य स्वास्थ्य सूचकांक' (स्टेट हेल्थ इंडेक्स) या 'नवाचार सूचकांक' (इनोवेशन इंडेक्स) में पिछड़े क्षेत्रों के संरचनात्मक ऐतिहासिक नुकसानों को महत्व (वेटेज) दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने और शहरी समूहों (अर्बन कांग्लोडिमरेट्स) की ओर बड़े पैमाने पर होने वाले असंगठित संकटग्रस्त प्रवासन (डिस्ट्रेस माइग्रेशन) को रोकने के लिए प्रस्तावित ठोस नीतिगत मॉडलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) एवं (ख) नीति आयोग ने 11 मार्च, 2026 को "राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई)" का दूसरा संस्करण जारी किया। एफएचआई राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का एक व्यापक, डेटा संचालित मूल्यांकन प्रदान करता है और साक्ष्य आधारित राजकोषीय नीति निर्माण का समर्थन करता है। यह राज्य के अपने राजस्व जुटाने को मजबूत करने, व्यय की गुणवत्ता में सुधार, प्रतिबद्ध व्यय को युक्तिसंगत बनाने, मध्यम अवधि के राजकोषीय योजना ढांचे को अपनाने, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों में सुधार, राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार और ऑफ बजट उधार की निगरानी जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है। विस्तृत कार्यप्रणाली, राज्यवार रैंकिंग और विश्लेषण https://niti.gov.in/sites/default/files/2026-03/Fiscal-Health-Index-2026.pdf. पर देखा जा सकता है।

(ग) नीति आयोग ने साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने तथा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक और भारत नवाचार सूचकांक सहित विभिन्न सूचकांक विकसित किए हैं। ये सूचकांक आधिकारिक डेटा स्रोतों से प्राप्त स्पष्ट रूप से परिभाषित पद्धतियों और संकेतकों पर आधारित हैं। यद्यपि संबंधित संरचनात्मक और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि संबंधित सूचकांक के लिए उपयुक्त भौगोलिक आकार, शासन और राजकोषीय विशेषताएं, इन सूचकांकों की पद्धतियों को मानकीकृत संकेतकों और पारदर्शी ढांचों का उपयोग करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वस्तुनिष्ठ तुलना को सुकर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(घ) भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस), कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन, नमो ड्रोन दीदी, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ), प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ) आदि को लागू कर रही है।

*****